रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 628
05 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण

628. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव निम्बालकरः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री हेमन्त पाटिलः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुराने, वर्तमान और उच्च तकनीक श्रेणी के संदर्भ में क्रमशः सैन्य उपकरणों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रक्षा बजट में किया गया आवंटन सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैन्य उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का उपयोग किया जा रहा हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षो के दौरान 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत की गई सभी रक्षा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर
रक्षा राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) सैन्य उपकरणों का प्राधिकार और नियंत्रण सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक आवश्यकता के अनुसार है । सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसे

सशस्त्र बलों को संक्रियात्मक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी की अवस्था में रखने के लिए किया जाता है । आधुनिकीकरण परियोजनाओं को मौजूदा रक्षा प्रापण प्रक्रिया (डीपीपी) के संदर्भ में सेवा पूंजीगत अधिग्रहण योजनाओं और वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं के अनुमोदन के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है । बजट अनुमानों/अनुपूरक/संशोधित अनुमानों के अंतर्गत आबंटित निधियों के आधार पर थलसेना सहित सेनाओं की संवेदनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । आबंटित निधियों का अधिकतम और पूर्ण उपयोग संक्रियात्मक क्रियाकलापों के लिए किया जाता है ।

(ग) और (घ): डीपीपी-2016 में स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं रक्षा उपकरण प्लेटफार्मों, प्रणालियों और उपप्रणालियों के विनिर्माण को बढ़ावा देकर सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ाने के लिए रक्षा प्रापण प्रक्रिया को सुप्रवाही तथा सरल बनाने पर जोर दिया जाता है । रक्षा प्रापण प्रक्रिया में एक नई बनाओ II प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें भारतीय उद्योग को अनुसंधान और विकास करने, रक्षा उपकरण की आपूर्ति हेतु स्वत: प्रस्तावों को प्रवर्तित करने और प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है । इसमें एमएसएमई और स्टार्ट अप सहित भारतीय उद्योग की सहभागिता के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरण के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में सामरिक भागीदारी संबंधी एक नीति भी प्रख्यापित की है ।

*****